RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 17 NOVEMBER TO 23 NOVEMBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 11 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सेंसेक्स 314 अंक टूटा, निफ्टी भी 17,900 से नीचे बंद Page 2

टोल टैक्स से सरकार को अभी कितनी आमदनी अगले 5 साल में किस लेवल पर पहुंचने का अनुमान Page 4

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अब 'पॉड होटल' की सुविधा Page 7

editoria!

बेहतर शासन पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रालयों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए - अनेक नयी पहल करते रहे हैं. शासन को पारदर्शिता के साथ सुचारु रूप से चलाना तथा सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को तय समय में अमल में लाना उनकी प्राथमिकता रही है. इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 77 सदस्यों को आठ विभिन्न समूहों में बांटा गया है. इन समूहों के गठन से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों की पांच लंबी बैठकें हुई. जिनमें शासन को अधिक सक्षम बनाने के उपायों पर चर्चा की गयी. प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ मिलकर कामकाज की समीक्षा तो करते ही रहते हैं, साथ ही, वे सचिवों के साथ भी विचार-विमर्श करते रहते हैं. इस नयी व्यवस्था में मंत्रियों के समूह युवा पेशेवर व दक्षलोगों की सेवा लेने के साथ सेवानिवृत्त हो रहे अनुभवी अधिकारियों से सलाह लेंगे तथा तकनीकी संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे. ऐसी ही कोशिशें मंत्रालयों के स्तर पर भी होंगी. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्रियों को मीडिया के साथ बात करने से कहीं अधिक ध्यान अपने काम पर देने की सलाह देते रहते हैं. पिछले मॉनसून सत्र में उन्होंने नये मंत्रियों से संसद में उपस्थित रहकर बहस करना सीखने का निर्देश दिया था. वर्तमान मंत्रिपरिषद में पहली बार मंत्री बने नेताओं की बड़ी संख्या है. अलग-अलग विषय पर ञ्ञ आधारित आठ समूहों के गठन से ऐसे मंत्रियों को ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत मदद मिलेगी. अंतिम चिंतन शिविर में विशेष रूप से उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था. माना जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों के प्रमुखों ने मंत्रियों से संसदीय व्यवस्था और उत्तरदायित्व के महत्व पर बातचीत की है. केंद्र सरकार की अहम योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति की जानकारी हर नागरिक आसानी से पा सके. इसके लिए सभी मंत्रालयों की वेबसाइटों पर प्राथमिकता से सूचना मुहैया कराने को इस नयी व्यवस्था में प्रमुखता दी गयी है. मंत्रियों और विभागों के बीच सूचना का आदानप्रदान सरल हो तथा परस्पर बैठकों व पत्राचार में कोई मुश्किल न आये. इस पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा. अनेक सरकारी योजनाओं में एक से अधिक ञ्ञ मंत्रालयों और विभागों की भूमिका होती है. आपस में ठीक से सामंजस्य और समन्वय न होने से उनके पूरा होने में अक्सर देरी हो जाती है. मंत्री समूहों के बनने तथा तकनीक के अधिकाधिक उपयोग से इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है. युवा प्रतिभाओं को शासन व्यवस्था से जोड़ना एक सराहनीय पहल है. इससे नयी दृष्टि और नयी ऊर्जा का संचार होगा. कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी और जवाबदेही मंत्रिपरिषद में निहित होती है. इसलिए मंत्रियों के बीच आपसी संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है. सब अपनी क्षमता से एक साथ कार्यशील होंगे, तभी प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' संकल्प को सही मायनों में साकार किया जा सकता है.

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल, डीजल की कीमतें स्थिर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों को अपरिवर्तित रखने के साथ उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल रही है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले दैनिक मूल्य बदलाव तंत्र के तहत बुधवार को लगातार 13वें दिन उनकी कीमतें स्थिर रहीं। दिल्ली में पेट्रोल की पंप कीमत 4 नवंबर को दिवाली के दिन सुबह 6 बजे गिरकर 103.97 रुपये प्रति लीटर हो गई, जो पिछले दिन 110.04 रुपये प्रति लीटर थी। राजधानी में डीजल की दरें भी 86.67 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहीं। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर है।

नवंबर के पहले सप्ताह में 11.77 रुपये प्रति लीटर की कमी के बाद 5.82 रुपये और डीजल 89.79 रुपये प्रति लीटर की गिरावट के बाद कोलकाता में भी ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत भी 101.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.43 रुपये प्रति लीटर पर जारी है। देशभर में और साथ ही ईंधन की कीमत

बुधवार को बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित रही, लेकिन स्थानीय करों के स्तर के आधार पर खुदरा दरें भिन्न हैं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें जो पिछले एक महीने में कई मौकों पर 85 डॉलर प्रति बैरल के तीन साल के उच्च स्तर को छू चुकी हैं, अब नरम होकर 82 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं। अमेरिकी इन्वेंट्री में वृद्धि ने कच्चे तेल की कीमतों को कम कर दिया है लेकिन ओपेक प्लस दिसंबर में उत्पादन में केवल क्रमिक वृद्धि पर निर्णय से कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं।

इससे तेल कंपनियों पर कीमते बढ़ाने का दबाव पड़ सकता है। कीमतों में कटौती और ठहराव से पहले, डीजल की कीमतों में पिछले 54 दिनों में से 30 बार दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 9.90 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई। पिछले 50 दिनों में से 28 बार पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं, इसके पंप की कीमत 8.85 रुपये प्रति लीटर है। 1 जनवरी, 2021 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ड्यूटी में कटौती से पहले 26 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था और केंद्र द्वारा शुल्क में कटौती का फैसला करने से पहले डीजल पर 31.8 रुपये और पेट्रोल पर 32.9 रुपये प्रति लीटर था।

ग्लोबल तेल कंपनियों के प्रमुख से मिलेंगे हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में ईंधन की कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा और उद्योग मंत्री सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एमडी और ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान अहमद अल जाबेर से अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत-यूएई सामरिक साझेदारी के समग्र ढांचे के भीतर ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी। भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक संयुक्त अरब अमीरात के तेल इंडस्ट्री के प्रमुखों के साथ यह बैठक भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों के रिकॉर्ड तेजी के बीच हो रही है। भारत अपनी 85 फीसदी तेल मांग और 55 फीसदी प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। पुरी ने पहले कहा था कि अगर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसका वैश्विक आर्थिक सुधार पर असर पड़ेगा।

भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा, ' यूएई के ऊर्जा और उद्योग मंत्री सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई के निमंत्रण पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 15 से 17 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे।' भारत ने हाल ही में तेल की ऊंची कीमत का मुद्दा उठाया था, जब ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो भारत यात्रा पर थे। भारत सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ इस मुद्दे को उठाता रहा है।

रुपया नौ पैसे की तेजी के साथ 74.37 प्रति डॉलर पर

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में सुस्ती के रुख के बावजूद विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया आरंभिक हानि से उबर गया और नौ पैसे की तेजी के साथ 74.28 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 74.51 के स्तर पर कमजोर रुख के साथ खुला और फिर कारोबार के अंत में डॉलर के मुकाबले नौ पैसे की तेजी दर्शाता 74.28 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपये का पिछला बंद भाव 74.37 रुपये प्रति डॉलर था। कारोबार के दौरान रुपये में 74.25 से लेकर 74.51 रुपये के दायरे में घटबढ़ हुई।

कोल इंडिया ने ई-नीलामी के जरिये बिजली क्षेत्र को 173.4 लाख टन कोयला आवंटित किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बिजली क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी योजना के तहत अप्रैल-सितंबर में 173.4 लाख टन कोयला आवंटित किया, जो सालाना आधार पर 72.1 प्रतिशत अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने इस योजना के तहत एक साल पहले इसी अवधि में 100.7 लाख टन कोयले का आवंटन किया था। हालांकि, सितंबर में बिजली क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत कोई कोयला आवंटित नहीं किया गया था। फॉरवर्ड ई-नीलामी के जरिये कोयला आवंटन का मकसद उन उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराना है, जो अपने परिचालन की योजना बनाने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से लंबी अवधि में सुनिश्चित रूप से आपूर्ति चाहते हैं।

News यू केन USE

गंभीर डॉलर संकट के बीच श्रीलंका ने बंद की एकमात्र तेल रिफाइनरी

कोलंबो। श्रीलंका ने देश में चल रहे गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के बाद सोमवार को अपनी एकमात्र तेल रिफाइनरी को 50 दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''सापूगस्कंद रिफाइनरी आज से 50 दिन के लिए बंद रहेगी।'' हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि रिफाइनरी के बंद होने से द्वीपीय देश में ईंधन की कमी नहीं होगी। गम्मनपिला ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में चल रहे विदेशी मुद्रा संकट के मद्देनजर रिफाइनरी को बंद करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, ''जब हम डॉलर के संकट से उबर जाएंगे, तो कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू हो जाएगा और रिफाइनरी परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा।'' मंत्री ने कहा कि सरकार ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के बजाय परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात जारी रखेगी।

रिजर्व बैंक ने 100 से अधिक अनावश्यक परिपत्र वापस लिए

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को नियमन समीक्षा प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 100 से अधिक अनावश्यक परिपत्रों को वापस ले लिया। जिन परिपत्रों को वापस लिया गया है, उनमें से कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में विदेशी निवेश, आरटीजीएस, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), और धन-शोधन रोधी (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) के मानकों संबंधित हैं। आरबीआई ने इस साल अप्रैल में नियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की थी। इस प्राधिकरण का मकसद नियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और दोहराव वाले निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां भी संभव हो विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना है।

सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किया चार्टर

नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वालों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बुधवार को निवेशक चार्टर जारी किया। इस चार्टर में निवेशकों के अधिकारों एवं दायित्वों का ब्योरा होने के साथ ही उन्हें प्रतिभूति बाजार में बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराने की कोशिश की गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक सार्वजनिक सूचना के मुताबिक इस चार्टर को तैयार करने का मकसद निवेशकों के हितों को सुरक्षित करना और उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित बाजार में निवेश में मदद पहुंचाना है। चार्टर में निवेशकों को निष्पक्ष एवं समान व्यवहार, समयबद्ध ढंग से शिकायतों का निपटारा किए जाने, सेबी से मान्यता-प्राप्त बाजार ढांचागत संस्थानों एवं मध्यवर्तियों से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हासिल करने का हकदार बताया गया है। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी तय करते हुए उन्हें 'करने योग्य' एवं 'नहीं करने योग्य' में बांटा है। सेबी ने कहा कि निवेशकों की शिकायतों का समय पर निपटान उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। सेबी अपने पोर्टल स्कोर्स के जरिये ऑनलाइन शिकायतों का निपटान करता है।

सेंसेक्स 314 अंक टूटा, निफ्टी भी 17,900 से नीचे बंद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में कमजोरी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 314 अंक टूट गया। बैंकिंग, तेल और गैस तथा फार्मा शेयरों में मुनाफावसूली के चलते प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे दिन करीब आधा प्रतिशत की गिरावट हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन नुकसान दर्शाते हुए 314.04 अंक यानी 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,008.33 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 60,426.61 के ऊपरी स्तर और 59,944.77 के निचले स्तर को छुआ। इसी तरह निफ्टी भी कारोबार के अंत में 100.55 अंक यानी 0.56 फीसदी टूटकर 17,898.65 पर आ गया।

सेंसेक्स में सबसे अधिक दो प्रतिशत की गिरावट एक्सिस बैंक में हुई। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक, भारती एयरटेल, टाइटन, डॉ रेड्डीज और एमएंडएम भी लाल निशान में रहे। दूसरी ओर मारुति सुजूकी, एशियन पेंट्स, पावरग्रिड और एनटीपीसी मुनाफे में रहने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''अमेरिका में खुदरा बिक्री के मजबूत आंकड़े वैश्विक बाजारों को प्रेरित करने में विफल रहे और घरेलू सूचकांक कारोबार के दौरान लाल निशान में दिखाई दिए। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में 4.2ङ्क थी, जो एक महीने पहले 3.1ङ्क रही थी। इससे मुद्रास्फीति को लेकर निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।'' नायर ने कहा कि एक रिपोर्ट में चिप और सेमी-कंडक्टर की कमी से जल्द राहत मिलने की बात कही गई, जिसके चलते दिन के कारोबार में ऑटो सेक्टर फोकस में था। सेक्टर के लिहाज से बीएसई रियल्टी, ऊर्जा, तेल और गैस, दूरसंचार और बैंकेक्स 1.79 फीसदी तक गिरे, जबकि बिजली, ऑटो, उपयोगिता और स्वास्थ्य देखभाल सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए।

व्यापक मिडकैप सूचकांक 0.21 फीसदी गिरकर बंद हुआ जबकि स्मॉलकैप सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा कि कारोबार की अंतिम घंटों में मुनाफावसूली के चलते बाजार में गिरावट हुई और कमजोर वैश्विक संकेतों से भी धारणा प्रभावित हो रही है। अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग, तोक्यो और सोल के शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए, जबकि शंघाई में कारोबार बढ़त के साथ समाप्त हुआ।

यूरोप के ज्यादातर शेयर बाजारों में मध्य सत्र के दौरान बढ़त थी। इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.90 प्रतिशत गिरकर 81.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

पीएम नरेंद्र मोदी का सरकारी विभागों को फरमान

CAG को उपलब्ध कराएं फाइलें और दस्तावेज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों से कहा कि कैग जो भी दस्तावेज, आंकड़े और फाइल मांगें, वे उसे उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। मोदी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय में मंगलवार को पहले ऑडिट दिवस को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे और सरकारी व्यय पर आपकी चिंताओं को हमने सकारात्मक तरीके से लिया है।

मोदी ने कहा कि कैग को महामारी के समय में अपनाए गए बेहतरीन उपायों और क्रमबद्ध सीखों का अध्ययन करना चाहिए और वैज्ञानिक एवं सशक्त लेखा परीक्षण से व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 'डेटा' ही सूचना है और आने वाले समय में हमारा इतिहास भी 'डेटा' के जरिए देखा और समझा जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कैग कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया।

कौटिल्य की परिकल्पना

इस मौके पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि आज इस दिन को हमने प्रथम ऑडिट दिवस के तौर पर मनाने के लिए चुना है। इस दिन का महत्व इस बात से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बंगाल, मद्रास एवं बंबई तीनों प्रेसीडेंसी के लेखा विभागों के विलय के बाद 16 नवंबर 1860 को प्रथम ऑडिटर जनरल ने कार्यभार ग्रहण किया था। हम इस दिन को हर साल ऑडिट दिवस के रूप में मनायेंगे।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो हमें सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखाओं में बेहतरी के लिए निरंतर खोज के माध्यम से खुद को फिर से समर्पित करने और सुशासन में योगदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कौटिल्य पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कोषाध्यक्ष के पद से अलग एक नियंत्रक-लेखापरीक्षक की भूमिका की कल्पना की थी। मौर्य काल में इसे अक्षपातालाध्यक्ष कहा जाता था। उनकी सोच थी कि इससे जवाबदेही एवं दक्षता बढ़ेगी और हितों के टकराव जैसी स्थिति में कमी आएगी।

देश कैसे हासिल कर पाएगा टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, RBI गवर्नर ने बताया

मुंबई। एजेंसी

महामारी की मार झेल चुकी अर्थव्यवस्था के तमाम वृहत संकेतक आर्थिक पुनरुद्धार के मजबूत होने का इशारा कर रहे हैं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कही। हालांकि, दास ने आर्थिक वृद्धि के टिकाऊ होने के लिए निजी पूंजी निवेश में वृद्धि को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था समुचित तेज रफ्तार से बढ़ने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन उसके लिए निजी पूंजी का निवेश बढ़ना जरूरी है। कई अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.5-10 प्रतिशत के बीच कर दिया है, लेकिन रिजर्व बैंक 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के अपने अनुमान पर टिका हुआ है। दास ने बैंकिंग क्षेत्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निवेश का माहौल सुधरने पर बैंकों को भी निवेश के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष से निवेश चक्र में तेजी आने की उम्मीद जताई है। वर्ष-2013 से ही अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी की आवक कम रही है। कई जानकारों का मानना है कि अगले वित्त वर्ष के मध्य से निजी निवेश में फिर से तेजी आ सकती है।

जुलाई-सितंबर में सुधरा बैंकों का ग्रॉस एनपीए दास ने बैंकों के बही खातों के बेहतर होने का जिक्र करते हुए कहा कि बैंकों का सकल फंसा कर्ज जुलाई-सितंबर की तिमाही में पहली तिमाही की तुलना में कम हुआ है। उन्होंने बैंकों से अपनी पूंजी प्रबंधन प्रक्रिया को बेहतर करने को भी कहा। गवर्नर ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि स्टार्टअप परिदृश्य में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और अरबों डॉलर की विदेशी पूंजी आई है।

टोल टैक्स से सरकार को अभी कितनी आमदनी

अगले 5 साल में किस लेवल पर पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में सड़कों और राजमार्गों के विकास का कार्य जोरों शोरों से जारी है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। देश का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई और पुणे के बीच बनाया गया था। देश में एक और महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसके 2023 में परिचालन में आने की उम्मीद है।

अब जब देश में हाइवेज और एक्सप्रेसवे की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि टोल प्लाजा की संख्या भी बढ़ेगी। टोल प्लाजा बढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आमदनी भी बढ़ेगी, यानी सरकार की तिजोरी में धनराशि बढ़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एनएचएआई को 'सोने की खान' करार दे चुके हैं। आइए जानते हैं कि अभी एनएचएआई की टोल टैक्स से कितनी कमाई है और अगले 5 सालों में इसके कहां पर पहुंचने का अनुमान है....नितिन गडकरी ने इसी साल सितंबर माह में बताया था कि अभी एनएचएआई की सालाना टोल आय 40,000 करोड़ रुपये के स्तर पर है। अगले पांच साल में यह बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी। मार्च 2020 तक देश में ॲ के 566 टोल प्लाजा थे। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ॲ का टोल कलेक्शन क्रमशः 27,682.89 करोड़ रुपये और 28,548.05 करोड़ रुपये रहा।

गडकरी का कहना है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परिचालन में आने और जनता के लिए खोले जाने के बाद केंद्र को हर महीने 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये का टोल राजस्व देगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 'भारतमाला परियोजना' के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। आठ लेन का यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात से होकर जाएगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी से देश की वित्तीय राजधानी के बीच यात्रा का समय मौजूदा के 24 घंटे से घटकर आधा यानी 12 घंटे रह जाएगा।फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन अक्टूबर में 21.42 करोड़ लेनदेन में रिकॉर्ड 3,356 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में फास्टैग से टोल कलेक्शन 19.36 करोड़ लेनदेन में 3,000 करोड़ रुपये रहा था। वहीं अगस्त में यह 20.12 करोड़ लेनदेन में 3,076.56 करोड़ रुपये रहा था। सरकार ने 15 फरवरी को मध्यरात्रि से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। यह एक्सप्रेसवे वर्तमान के 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' और मौजूदा 'यमुना एक्सप्रेसवे' से भी जुड़ जाएगा। युद्ध की स्थिति या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यहां वायुसेना के विमानों की इमर्जेंसी लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनी है। एक्सप्रेसवे की कुल लागत 22,494 करोड़ रुपये है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की कीमत भी शामिल है।

मप्र सरकार ने भोपाल, इंदौर के हवाई अड्डों पर एटीएफ पर कर घटाकर चार प्रतिशत किया

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर विमान ईंधन एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को घटाकर चार प्रतिशत करने का फैसला किया है। इस फैसले से हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि वर्तमान में भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर एटीएफ पर वैट 25 प्रतिशत था। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इसे कम करने का निर्णय लिया और अब यह चार प्रतिशत हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो हवाई अड्डों, जहां एटीएफ पर 4 प्रतिशत वैट है, की तरह भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर भी इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

अधिकारी ने कहा कि इस कदम से विमानन कंपनियां विमान किराया कम करने, प्रदेश से और उड़ानें शुरु करने और हवाई यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए प्रेरित होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले मांग की थी कि मध्य प्रदेश में एटीएफ पर वैट को एक समान चार प्रतिशत की दर पर किया जाए ताकि उनके गृह राज्य में और उड़ानें संचालित हो सकें।

देश में इस्पात की मांग 2024-25 तक बढ़कर 16 करोड़ टन पर पहुंचेगी : मंत्री

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में इस्पात की खपत वित्त वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 16 करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को गुजरात के नर्मदा जिले में इस्पात पर सांसदों की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बैठक में मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश में तैयार इस्पात की कुल खपत 9.62 करोड़ टन थी। 2024-25 तक इसके बढ़कर 16 करोड़ टन पर पहुंच जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा, ''सरकार देश में इस्पात उत्पादन क्षमता और मांग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।'' सिंह ने कहा कि सरकार ने हाल में 'गति शक्ति' मास्टर प्लान की घोषणा की है। इससे देश में इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास में इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बुनियादी ढांचा, निर्माण, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, वाहन और रक्षा क्षेत्र में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इस बैठक में कई सांसदों ने भाग लिया।

अपोलो टायर्स अपने टायरों के दाम तीन से पांच प्रतिशत बढ़ाएगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रमुख टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स जिंस कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में घरेलू बाजार में अपने टायरों के दाम तीन से पांच प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। अपोलो टायर्स के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नीरज कंवर ने सोमवार को विश्लेषकों से कहा कि सितंबर तक कंपनी ने टायरों के दाम औसतन नौ प्रतिशत बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा, ''इस तिमाही (अक्टूबर और नवंबर) में भी हम कीमतों में तीन से पांच प्रतिशत की वृद्धि करेंगे।'' चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में अपोलो टायर्स का एकल शुद्ध लाभ 59 प्रतिशत घटकर 89.65 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 216.24 करोड़ रुपये रहा था। एकल आधार पर दूसरी तिमाही में कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 3,649.71 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 2,911.57 करोड़ रुपये थी।

RBI की नई योजना, जानिए कैसे आप बैंक और दूसरे संस्थानों के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं शिकायत?

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना शुरू की है। यह एक तरह से 'एक देश-एक लोकपाल' सिस्टम है, जिसका मकसद बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFC) और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ ग्राहकों की ओर से आने वाले शिकायत के निवारण सिस्टम को मजबूत बनाना है। सर्वत्र टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, वाइस-चेयरमैन और MD मंदार अगाशे कहते हैं, 'नए-नए तरह के पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी आने के चलते 'एक देश-एक लोकपाल' सिस्टम यूजर्स के लिए काफी अहम बूमिका निभाएगा। ग्राहक अब किसी भी बैंक, पेमेंट सिस्टम के खिलाफ एक ही जगह शिकायत दर्ज करा सकेंगे, उसे ट्रैक कर सकेंगे और उस पर फीडबैक हासिल कर सकेंगे। इससे उनके समय के साथ धन की भी बचत होगी. आइए स्टेप-दर-स्टेप प्रक्रिया के जरिए जानते हैं कि कस्टमर लोकपाल सिस्टम में कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जानें कहां करें शिकायत

आप लोकपाल के पास कई तरह से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट https://cms.Ri.org.in पर जाएं. या CRPC@Ri.org.in पर ईमेल के जरिए या टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म भरकर और चंडीगढ़ में आरबीआई द्वारा स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रॉसेसिंग सेंटर' को भेजकर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

शिकायत की प्रति अपलोड करना होगा

RBI की CMS वेबसाइट पर, शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के साथ वेरिफाई करना होगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी भरें और उस संस्था का चयन करें जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है। उस तारीख के साथ शिकायत का जानकारी दें, जिस तारीख को आपने पहली बार उस संस्था के खिलाफ शिकायत दायर किया था, फिर शिकायत की प्रति अपलोड करें।

देनी होगी ये जानकारी

शिकायत दर्ज करने के लिए कार्ड नंबर/लोन/बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान करें। फिर शिकायत की कैटेगरी चुनें। उदाहरण के लिए, लोन और एडवांस या मोबाइल बैंकिंग. आप ड्रॉप-डाउन मेनू से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। फिर एक उपयुक्त सब-कैटेगरी का चयन करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने सब-कैटेगरी 1 में लिए गए फीस के संबंध में एक शिकायत का चयन किया है, फिर ड्रॉप-डाउन में मेनू, आपको शिकायत का कारण चुनने की जरूरत होगी, जैसे क्रेडिट कार्ड जारी आदि. शिकायत का तथ्यात्मक विवरण प्रदान करें. विवाद की राशि और मांगे गए मुआवजे (यदि कोई हो) का उल्लेख करें। शिकायत की समरी देखें और फिर उसे सबमिट करें. अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए शिकायत की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करें और सेव करें।

'मेक इन इंडिया' में बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं महिलाएं : अध्ययन

नयी दिल्ली। एजेंसी

महिला पेशेवर अधिक जिम्मेदारियां लेने के साथ नीति निर्माण, परिचालन, विनिर्माण तथा इंजीनियरिंग सेवा क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के इन प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समावेश में मदद के लिए अनुकूल नीतियों और व्यवहार की जरूरत है।

जीई के बिलॉन्ग-2021 सम्मेलन में जारी जीई और अवतार की शोध रिपोर्ट से पता चला कि महिला पेशेवर अधिक जिम्मेदारियां लेना चाहती हैं और 'मेक इन इंडिया' में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं। शोध में यह भी पता चला कि 84.4 प्रतिशत पुरुष प्रतिभागियों का मानना था कि परिचालन, विनिर्माण और इंजीनियरिंग सेवा क्षेत्रों में अधिक महिलाओं को रोजगार देने से उल्लेखनीय लाभ होगा। अवतार के अनुसार इन क्षेत्रों में फिलहाल केवल 12 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह शोध जीई द्वारा कराया गया और अवतार ने इसे सितंबर और अक्टूबर, 2021 के दौरान पूरा किया। इस दौरान करीब 500 पेशेवरों (पुरुषों और महिलाओं) से राय ली गई। जीई दक्षिण एशिया के आईएडंडी काउंसिल लीडर शुक्ल चंद्र ने कहा, ''जीई सभी तरह की विविधताओं पर मजबूती से ध्यान दे रही है। यह अध्ययन हमें और हमारी सहयोगी कंपनियों को परिचालन, विनिर्माण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के प्रबंधन में लैंगिक विविधता लाने में मदद करेगा।''

एचडीएफसी बैंक 2,000 कार्यशालाएं आयोजित करेगा

ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताएगा

मुंबई। एजेंसी

निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए अगले चार महीनों में 2,000 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित करने जा रहा है। बैंक ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि इस अभियान में बैंक ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। खासतौर पर युवा ग्राहकों को वित्तीय जोखिमों के बारे में बताया जाएगा। बैंक का इरादा स्कूल और कॉलेजों के युवाओं को इस बारे में जागरूक करने का है।

एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन ने कहा, ''डिजिटलीकरण ने बैंक ग्राहकों को बेशुमार सहूलियत दी है। लेकिन इसके साथ साइबर धोखाधड़ी के जोखिम भी बढ़ गए हैं। धोखेबाज लगातार सीधे-सरल ग्राहकों को फंसाने की फिराक में रहते हैं।''

इस अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत नीति आयोग के विशेष सचिव के. राजेश्वर राव ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के सह-समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत भी मौजूद थे।

कोरोना काल में भारत को मंगाना पड़ा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खाद्य तेल, जानिए क्या रही वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना काल में देश में खाद्य तेलों का आयात रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2020-21 में भारत ने विदेशों से 1.17 लाख करोड़ रुपये (15.71 अरब डॉलर) का खाद्य तेल मंगाया जो पिछले साल की तुलना में 63 फीसदी अधिक है। Solvent Extractors' Association of India (SEA) ने यह जानकारी दी है। वॉल्यूम टर्म्स में भारत का आयात 2020-21 मार्केटिंग वर्ष में 135.3 करोड़ टन रहा जो पिछले साल 135.2 करोड़ टन रहा था। विदेशों में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से भारत का आयात बिल बढ़ा। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत के इम्पोर्ट में पाम ऑयल की मात्रा सबसे अधिक है। पाम ऑयल अभी रेकॉर्ड स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केटिंग वर्ष 2020-21 में भारत का पाम ऑयल इम्पोर्ट 15.2 फीसदी बढ़कर 83.2 लाख टन पहुंच गया। डीडीए की 15 हजार फ्लैट्स की स्कीम पर गुड न्यूज, क्या होगा रेट, मिल गया संकेत

6 महीने में 3 बार आयात शुल्क में कटौती

देश में खाद्य तेल की कीमत रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और इसमें कमी लाने के लिए सरकार पिछले 6 महीने में 3 बार खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती की है। ऍ के मुताबिक मार्केटिंग वर्ष 2020-21 में भारत में सोयाबीन तेल का आयात 15 फीसदी की गिरावट के साथ 28.7 लाख टन पहुंच गया जबकि सनफ्लावर ऑयल का आयात भी करीब एक चौथाई गिरकर 19 लाख टन रह गई।

भारत पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदता है, सोयाबीन तेल का आयात अर्जेंटीना और ब्राजील से किया जाता है। भारत सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से मंगाता है। ऍ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीवी मेहता ने कहा कि नए मार्केटिंग वर्ष में भारत के वेजिटेबल ऑयल आयात में मामूली गिरावट आ सकती है। इसकी वजह यह है कि देश में सोयाबीन, मूंगफली और रेपसीड की घरेलू आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। खाद्य तेलों का मार्केटिंग वर्ष 1 नंवबर से 31 अक्टूबर तक है। मेहता ने कहा कि कीमतों के रेकॉर्ड पर पहुंचने से मांग में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में पाम ऑयल के आयात में कमी आ सकती है क्योंकि हाल के महीनों में इसकी कीमत में काफी तेजी आई है। इससे सोयाबीन तेल और सनफ्लावर ऑयल के आयात में तेजी आ सकती है।

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अब 'पॉड होटल' की सुविधा

जानें क्या होता है यह और कितना रहेगा चार्ज

मुंबई। एजेंसी

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला पॉड होटल (Pod Hotel) खुल गया है। इसमें भारतीय रेलवे (Indian Railways) के यात्री और यहां तक कि आम लोग भी अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर आधुनिक विश्राम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। IRCTC, भारतीय रेलवे के सहयोग से पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी बनी है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने दक्षिण मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से डिजिटल तरीके से किया। मंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से विभिन्न यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला पॉड होटल (Pod Hotel) खुल गया है। इसमें भारतीय रेलवे (Indian Railways) के यात्री और यहां तक कि आम लोग भी अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर आधुनिक विश्राम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ध्ंऊण, भारतीय रेलवे के सहयोग से पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी बनी है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने दक्षिण मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से डिजिटल तरीके से किया। मंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से विभिन्न यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। पॉड होटल में कई छोटे बिस्तर वाले कैप्सूल होते हैं और यह यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफायती आवास प्रदान करता है। पॉड होटल को कैप्सूल होटल भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार, यात्रियों को अब मुंबई सेंट्रल पहुंचने पर एक पूरी तरह से नई बोर्डिंग सुविधा का अनुभव होगा। पॉड होटल को सबसे पहले जापान में विकसित किया गया था। पॉड होटल उन मेहमानों के लिए किफायती, बुनियादी रात भर आवास की सुविधा प्रदान करते हैं, जिन्हें पारंपरिक होटलों द्वारा पेश किए जाने वाले बड़े, अधिक महंगे कमरों की जरूरत नहीं होती है या जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं।

कितना चार्ज और क्या सुविधाएं

पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटों के लिए 999 रुपये प्रति व्यक्ति और 24 घंटों के लिए 1,999 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान करना होगा। प्रत्येक पॉड रूम में मुफ्त वाई-फाई, लगेज रूम, टॉयलेटरीज, शॉवर रूम, सामान्य क्षेत्रों में वॉशरूम उपलब्ध होंगे। पॉड के अंदर, मेहमान टीवी, छोटे लॉकर, मिरर, एडजस्टेबल एयर कंडीशनर और एयर फिल्टर वेंट, रीडिंग लाइट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर लाइट, मोबाइल चार्जिंग, स्मोक डिटेक्टर, डीएनडी इंडिकेटर भी हैं।

तीन तरह के पॉड्समुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन (Mumbai Central Railway Station) पर पॉड होटल सुविधा कुल 48 पॉड्स की पॉड इन्वेंट्री प्रदान करती है। पॉड्स की 3 श्रेणियां शामिल हैं, जैसे कि क्लासिक पॉड्स, केवल लेडीज, प्राइवेट पॉड्स और डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी एक पॉड। इसमें 4 फैमिली पॉड्स भी शामिल हैं जो 4 सदस्यों के परिवार के रहने की पूर्ति करते हैं। पॉड सुविधा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर स्टेशन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित है और लगभग 3000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक मेजेनाइन फर्श के साथ फैली हुई है।

मैसर्स अर्बन पॉड होटल्स ने किया है तैयार

पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम

(Pod Concept Retiring Room) सुविधा को अनुबंध के आधार पर मैसर्स अर्बन पॉड होटल्स द्वारा सौंपा गया है। यह भारत में इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले पहली कंपनी है। आईआरसीटीसी (IRCTC) ने ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 9 साल के लिए POD कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम की स्थापना, संचालन और प्रबंधन का ठेका दिया है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

भारत से सोया खली निर्यात अक्टूबर में 78 प्रतिशत घटकर 30,000 टन पर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ऊंची कीमतों के चलते वैश्विक मांग में कमी के कारण भारत से अक्टूबर के दौरान सोया खली का निर्यात करीब 78 प्रतिशत घटकर महज 30,000 टन पर सिमट गया। पिछले साल अक्टूबर में देश से 1.35 लाख टन सोया खली का निर्यात गया था। प्रसंस्करणकर्ताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने बताया, ''अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोया खली के भाव अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना के इस उत्पाद के मुकाबले ऊंचे बने हुए हैं। भारतीय सोया खली की मांग में गिरावट का सबसे प्रमुख कारण यही है।''

गौरतलब है कि अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादकों के रूप में होती है। पाठक ने बताया कि अक्टूबर के दौरान देश के तेल संयंत्रों में सोया खली का उत्पादन करीब 37 प्रतिशत गिरकर 4.79 लाख टन रह गया। अक्टूबर, 2020 में घरेलू संयंत्रों में सोयाबीन का तेल निकालने से 7.58 लाख टन सोया खली बनी थी। उन्होंने बताया कि देश की मंडियों में नयी फसल की आवक के बीच मांग बढ़ने से सोयाबीन के भाव ऊंचे बने हुए हैं जिससे प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा इस तिलहन की खरीद प्रभावित हुई है। संयंत्रों में सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचने वाले उत्पाद को सोया खली कहते हैं। यह उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। इससे सोया आटा और सोया बड़ी जैसे खाद्य पदार्थों के साथ पशु आहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है।

हीरो इलेक्ट्रिक ने एक लाख चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 'चार्जर' से हाथ मिलाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

हीरो इलेक्ट्रिक ने तीन साल में देशभर में एक लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बेंगलुरु की ईवी चार्जिंग स्टार्टअप 'चार्जर' से हाथ मिलाया है। इस भागीदारी के पहले साल में चार्जर देश के शीर्ष 30 शहरों में 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। देश की प्रमुख दोपहिया कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि स्टार्टअप कंपनी चार्जर हीरो इलेक्ट्रिक की डीलरशिप में किराना चार्जर लगाएगी। इससे उपभोक्ता सुगमता से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सोहिंदर गिल ने कहा, ''हमारा मानना है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के विकास के लिए एक तेजतर्रार और बेहतर ढांचागत नेटवर्क जरूरी है। इस भागीदारी से देश में ईवी की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ताओं को आसानी से अपनी वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिल पाएगी। इस भागीदारी के तहत चार्जर द्वारा लगाए गए चार्जिंग स्टेशनों पर स्लॉट की बुकिंग और भुगतान का एकीकरण किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी चार्जिंग ढांचे के विस्तार पर काम कर रही है।

श्री हनुमानजी को खुश करने के 10 शुभ उपाय

हनुमानजी की पूजा मंगलवार, त्रयोदशी, चतुर्दशी और खास दिनों होती है। हिन्दू धर्म के सबसे जाग्रत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमत्र हनुमानजी की कृपा जिस पर बरसरना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दस दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। आओ जानते हैं कि उन्हें किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है।

1. **हनुमान चालीसा :** प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढें। वह भी एक ही जगह बैठकर।
2. **तीन कोनों वाला दीपक :** प्रतिदिन हनुमानजी के समक्ष तीन कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो।
3. **चौला चढ़ाएं :** जब भी इच्छा हो हनुमानजी को चौला चढ़ाएं। इसमें जनेऊ, लंगोट, सिंदूर, तुलसी की माला, ध्वज, चमेली का तेल, लाल फूल आदि सामग्री होती है।
4. **हनुमानजी का जाप करें :** 'ॐ श्री हनुमंते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें या साबरमंत्र को सिद्ध करें।
5. **श्रीराम का जाप करें :** प्रतिदिन श्रीराम जी के नाम का विधिवत जाप करें।
6. **सुंदरकाण्ड पढ़ें :** माह में एक बार सुंदरकांड और बजरंगबाण का पाठ करें।
7. **भोग लगाएं :** हनुमानजी को मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर पंच मेवा, केसरिया बूंदी लड्डू, इमरती, बेसन के लड्डू, चूरमा, रोठ, मालपुआ या मलाई-मिश्री के लड्डू का भोग लगाएं।
8. **हनुमान पूजा :** प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर विधिवत रूप से हनुमानजी की पूजा करें। यदि आप घोर संकट से घिरे हैं या आप हनुमानजी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं तो फिर आपको मांस, मदिरा और सभी तरह का व्यवसन त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन विधि-विधान से हनुमानजी की पूजा या उनके मंत्र या नाम का जप करना चाहिए। हनुमानजी के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता की भी पूजा अच्छे से करें।
9. **पान का बीड़ा :** अपने सुनी होगी एक प्रचलित लोकोक्ति 'बीड़ा उठाना'। इसका अर्थ होता है- कोई महत्वपूर्ण या जोखिमभरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमानजी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा-पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए मनचाहा वरदान।
10. **गुड़-चने का प्रसाद :** हनुमानजी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमानजी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमानजी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज्यादा मिलती है लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है।

चातुर्मास समाप्त, जानिए आगामी दो माह में शुभ विवाह की तारीखें

हिन्दू धर्म के अनुसार चातुर्मास Chaturmas 2021 वह चार महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर, कार्तिक शुक्ल एकादशी पर समाप्त होता है। चातुर्मास के चार महीने यानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह तक चार्तुमास जारी रहता है।

जब चातुर्मास का आरंभ होता है तो उसे 'देवशयनी एकादशी' और जब चातुर्मास समाप्त होता है तो 'देवोत्थान या देवउठनी एकादशी' कहा जाता है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये माह महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति और वातावरण भी अच्छा रहता है।

इन दिनों व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के चार महीने को हिन्दू धर्म में 'चातुर्मास या चौमासा कहा गया है। इस समयावधि को व्रतों का माह भी कहा जाता है क्योंकि उक्त चार माह में हमारी पाचनशक्ति कमजोर पड़ जाती है और भोजन और जल में बैक्टीरिया बढ़ जाते है। अतः इन दिनों उपवास रखना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

चातुर्मास समाप्ति होने के बाद ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते है। देवउठनी एकदशी के बाद सभी शुभ कार्य, जैसे मांगलिक विवाह Shubh Vivah Muhurat, नामकरण संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे कार्य शुरू हो सकेंगे। चातुर्मास में वर्जित माने गए सभी मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी के बाद जो आरंभ हो जाएंगे। आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी से शुभ मांगलिक विवाह का शुभारंभ हो जाता है। इस बार 14-15 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर के महीने में केवल 19, 20, 21, 26, 28, 29 व 30 इन तारीखों पर ही शुभ विवाह मुहूर्त हो सकेंगे और दिसंबर माह में 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 तारीख को आखिरी विवाह मुहूर्त है। इस हिसाब यदि देखा जाए तो आगामी 2 महीनों में बहुत ही कम शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इसके बाद अगले वर्ष यानी 2022 में 15 जनवरी से पुनः शुभ विवाह मुहूर्त प्रारंभ हो सकेंगे।

भारत में इन जगहों पर दिखाई देगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इन राशि वालों को होगा बड़ा लाभ

इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इसी महीने लगने जा रहा है, जिसका आपकी राशि पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है. ये आपके जीवन में कुछ परिवर्तन भी लेकर आ सकता है. 19 नवंबर को लगने जा रहे इस चंद्रग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव बेहद कम रह सकता है. साल का आखिरी चंद्र ग्रहण तुला, कुंभ और मीन राशि वालों पर शुभ प्रभाव डालेगा. इस दौरान आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. करियर में अच्छी सफलता मिलने के आसार रहेंगे.

भारत में नवंबर का चंद्र ग्रहण कब और कहां देखना है?

चंद्र ग्रहण का आंशिक चरण सुबह 11:34 बजे शुरू होगा और 05:33 बजे घ्एऊ पर समाप्त होगा. चंद्रोदय के तुरंत बाद, ग्रहण के आंशिक चरण की समाप्ति अरुणाचल प्रदेश और असम के चरम पूर्वोत्तर भागों से दिखाई देगी. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, चंद्रग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा और चांद का 97 फीसदी हिस्सा लाल दिखाई देगा.

सदी का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक, चंद्र ग्रहण- 3 घंटे, 28 मिनट और 23 सेकंड तक रहेगा, जो 2001 से वर्ष 2100 के बीच 100 वर्षों में किसी भी अन्य ग्रहण से अधिक लंबा होगा. नासा ने बताया है कि 21वीं सदी में पृथ्वी पर कुल 228 चंद्र ग्रहण होंगे.

इन राशियों पर ग्रहण का पड़ेगा शुभ प्रभाव

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण तुला, कुंभ और मीन राशि वालों पर शुभ प्रभाव डालेगा. इस दौरान आपको करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

तुला राशिः इस राशि वालों पर ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ने के आसार हैं. आपका भाग्योदय होने की प्रबल संभावना है. नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा. धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं.

कुंभ राशिः इस राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं. चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है. बाधाएं कम आएंगे. धन लाभ के संकेत हैं. करियर में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है. नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है.

मीन राशि : मीन राशि के जातकों को भी ये चंद्र ग्रहण अच्छे संकेत दे रहा है. इस राशि के जातकों को भी धन-संपत्ति के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है. आय में वृद्धी या पदोन्नति का समाचार मिल सकता है. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी और आय के नये स्त्रोत बनने की संभावना है.

हर मुश्किल आसान कर देंगे गुरु नानक देव के अमूल्य दोहे

शुक्रवार, 19 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती है। गुरु नानक देव सिखों के सबसे प्रसिद्ध गुरु और सिख धर्म के संस्थापक है। यहां पढ़ें उनके अमूल्य दोहे...

अपने ही सुखसों सब लागे, क्या दारा क्या मीत?
मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सों बाध्यौ चीत।
अंतकाल संगी नहिं कोऊ, यह अचरज की रीत?

मन मूरख अजहूं नहिं समुझत, सिख दै हारयो नीत।
नानक भव-जल-पार परै जो गावै प्रभु के गीत?

एक ओंकार सतनाम, करता पुरखु निरभऊ।
निरबैर, अकाल मूरति, अजूनी, सैभं गुर प्रसादि ।।
हुकमी उत्तम नीचु हुकमि लिखित दुखसुख पाई अहि।
इकना हुकमी बक्शीस इकि हुकमी सदा भवाई अहि ?

सालाही सालाही एती सुरति न पाइया।
नदिआ अते वाह पवहि समुंदि न जाणी अहि ?

पवणु गुरु पानी पिता माता धरति महतु।
दिवस रात दुई दाई दाइआ खेले सगलु जगतु ?

धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिओ अपनाई।
तन छूटै कुछ संग न चालै, कहा ताहि लपटाई?
दीन दयाल सदा दुःख-भंजन, ता सिउ रुचि न बढाई।
नानक कहत जगत सभ मिथिआ, ज्यों सुपना रैनाई?

जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने अपने कारोबार की शुरुआत के 100 हफ़्ते के भीतर एक महीने में 100 करोड़ रुपये की बिक्री के आंकड़े को पार किया

कंपनी वित्त-वर्ष 22 में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है

वित्त-वर्ष 22 की पहली छमाही में डेकोरेटिव बिजनेस में तीन गुना की बढ़ोतरी जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने सभी कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प प्रदान किए

मुंबई। पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार, मांग में वृद्धि तथा ग्राहकों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से, भारत में सबसे अधिक पर्यावरण-अनुकूल पेंट्स का निर्माण करने वाली एवं 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्ति वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा, जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने अक्टूबर 2021 में 100 करोड़ रुपये की मासिक बिक्री (जेएसडब्ल्यू पेंट्स की 100 में 100 उपलब्धियां) के आंकड़े को पार किया। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस प्रकार जेएसडब्ल्यू पेंट्स सर्वाधिक तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय पेंट कंपनी बन गई है। 100 करोड़ रुपये मासिक बिक्री को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, जेएसडब्ल्यू पेंट्स वित्त-वर्ष 22 में 1,000 करोड़ रुपये के राजस्व के आंकड़े को पार करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वित्त-वर्ष 22 की पहली छमाही में, कंपनी ने साल-दर-साल के आधार पर लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान, कंपनी के डेकोरेटिव बिजनेस के आकार में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है और इसके साथ ही यह कारोबार के संचालन के 100 हफ़्ते के भीतर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाली एकमात्र भारतीय पेंट कंपनी बन गई है। राष्ट्रीय स्तर की एक कंपनी के रूप में, जेएसडब्ल्यू पेंट्स अपने सभी कर्मचारियों के लिए जेएसडब्ल्यू पेंट्स क्षितिज ऐंध्ह्र-2021 नामक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना की शुरुआत करके भारत सरकार के 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम को पूरे जोश व उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहा है। पहली बार किसी भारतीय पेंट्स कंपनी ने एक ESOP योजना की है, जिसके तहत प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी के इक्विटी शेयर प्राप्त होंगे। क्षितिज ESOP-2021 योजना के माध्यम से कंपनी प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान करती है और उन्हें सशक्त बनाती है ताकि वे व्यवसाय के भविष्य के विकास को आकार देकर अपने साथ-साथ जेएसडब्ल्यू पेंट्स की अहमियत को और बढ़ा सकें।

अपने व्यवसाय के विकास और ESOP योजना की शुरुआत के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री पार्थ जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जेएसडब्ल्यू पेंट्स, ने कहा, 'मौजूदा वित्त-वर्ष की पहली छमाही के दौरान हमारे व्यवसाय ने राजस्व और मार्जिन में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सही मायने में उपभोक्ताओं पर केंद्रित इस पहले व्यवसाय का देशभर के ग्राहकों ने तहे दिल से स्वागत किया है, और यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे द्वारा बाजार में उतारे गए उत्पादों को देश भर में ग्राहकों ने काफी पसंद किया है और हम सभी जेएसडब्ल्यू पेंट्स के उज्ज्वल भविष्य के लिए आशान्वित हैं। परिवार के लिए पूरी तरह सुरक्षित हमारे उत्पाद, 'किसी भी रंग के लिए एक कीमत' की पेशकश तथा हमारे सरल, सुनिश्चित और तेज समाधान सचमुच जेएसडब्ल्यू पेंट्स को भारतीय बाजार में सबसे पसंदीदा विकल्प बना रहे हैं। हमारे कारोबार के संचालन के 100 हफ़्ते के भीतर मासिक बिक्री में 100 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल करना, वास्तव में हमारी पूरी टीम द्वारा अपने कर्तव्यों की सीमा से परे जाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम सभी एकजुट होकर जेएसडब्ल्यू पेंट्स को भविष्य की पेंट कंपनी के रूप में तैयार कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट्स क्षितिज ESOP-2021 योजना के तहत दिए गए स्टॉक विकल्प, हमारी टीम के प्रत्येक सदस्य को हमारी विकास यात्रा के अगले चरण में समान रूप से भागीदारी के लिए सशक्त बनाएंगे। हम सभी दर्जे के अपने सामान्य कर्मचारियों को ये स्टॉक विकल्प दे रहे हैं। यह तो सिर्फ जेएसडब्ल्यू पेंट्स के सफर की शुरुआत है और हमने इसे एक ऐसी कंपनी बनाने का संकल्प लिया है जिससे उद्योग जगत को ईर्ष्या होगी।'

श्री ए. एस. सुंदरेशन, ज्वाइंट एमडी एवं सीईओ, जेएसडब्ल्यू पेंट्स, ने कहा, 'महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, पिछले 100 हफ़्तों में हमारी प्रगति, सही मायने में हमारे ग्राहकों द्वारा 'एनी कलर वन प्राइस' जैसी अनोखी विचारधारा को स्वीकार करने का प्रमाण है। हमारी टीम के ज्यादातर सदस्यों की आयु 30 साल से कम है, और ऐसी युवा टीम ने स्टार्ट-अप की मानसिकता के साथ इतने कम समय में 100 करोड़ मासिक बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता पाई है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स क्षितिज ESOP-2021 उनके प्रयासों का सम्मान करता है और उन्हें हर दिन एक नए विचार के साथ इस बदलाव को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।'

जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपने सभी व्यवसायों में स्टॉक विकल्प जारी कर रहा है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी कंपनी की व्यवसायिक सफलता से लाभान्वित हो सके। इसने एक व्यापक ऐंध्ह्र योजना की शुरुआत की है ताकि कर्मचारियों को धन सृजन का अवसर प्राप्त हो सके, तीव्र गति से विकास के लिए बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिले तथा कर्मचारियों को जेएसडब्ल्यू परिवार का हिस्सा बनने पर गर्व का अनुभव हो। इससे पहले, समूह ने स्टील तथा ऊर्जा व्यवसायों में अपने सभी कर्मचारियों के लिए स्टॉक विकल्प की शुरुआत की है। अब यह कंपनी पेंट्स कारोबार में भी स्टॉक विकल्प पेश कर रही है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स अपने कर्मचारियों को धन-सृजन का अवसर प्रदान करके उनके साथ लंबे समय तक कायम रहने वाले संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है, जो खुद को कंपनी के विकास रूपी पहिए का महत्वपूर्ण घटक मानेंगे क्योंकि इस कंपनी में उनकी भी भागीदारी होगी।

निर्माण सामग्री के दाम नहीं घटे, तो 10 से 15 प्रतिशत तक महंगा हो जाएगा घर खरीदना : क्रेडाई

नयी दिल्ली। एजेंसी

रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई ने सीमेंट और इस्पात की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताई है। क्रेडाई ने कहा है कि अगर कच्चे माल के दाम नीचे नहीं आए, तो आवासीय संपत्तियों की कीमतें 10 से 15 प्रतिशत बढ़ सकती हैं। उद्योग निकाय ने सरकार से कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का सुझाव दिया। कनफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने कहा कि निर्माण में इस्तेमाल किये जाने कच्चे माल की कीमतों में जनवरी, 2020 से लगातार वृद्धि हो रही है। निकाय ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों और श्रमबल की कमी के कारण निर्माण में देरी से पिछले 18 महीनों में निर्माण लागत में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्रेडाई ने एक बयान में कहा, ''कच्चे माल की कीमतें निकट भविष्य में नहीं घटती हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि निर्माण की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए आवासीय संपत्तियों की कीमतें 10-15 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी।'' क्रेडाई के अध्यक्ष हर्ष वर्धन पटोदिया ने कहा, ''हम पिछले एक साल में कच्चे माल की कीमतों में लगातार तेज वृद्धि देख रहे हैं और निकट भविष्य में उनके नीचे आने या स्थिर होने संभावना नहीं है।'' उन्होंने कहा कि ऐसे में बिल्डर बढ़ती लागत का बोझ नहीं उठा पाएंगे और वे इसे घर खरीदारों पर डालेंगे।

बीएमडब्ल्यू ने 220आई 'ब्लैक शैडो' संस्करण उतारा, कीमत 43.5 लाख रुपये

नयी दिल्ली। एजेंसी

जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारतीय बाजार में 2 श्रृंखला की ग्रैन कूपे का एक विशेष संस्करण पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 43.5 लाख रुपये है। बीएमडब्ल्यू की नयी कार 220आई 'ब्लैक शैडो' विशेष संस्करण को चेन्नई स्थित संयंत्र में स्थानीय स्तर पर बनाया गया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह मॉडल दो लीटर के चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ उतारा गया है, जो इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और रफ्तार को सुनिश्चित करता है। कंपनी ने दावा किया दो लीटर का चार सिलेंडर का इंजन 190 की हॉर्स पावर पैदा करता है, जिससे यह मॉडल केवल 7.1 सेकंड में शून्य से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है।

डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत को खाद्य भंडारण संबंधी प्रावधान में बदलाव की उम्मीद

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 30 नवंबर से शुरू हो रही मंत्री-स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर एक स्थायी समाधान तलाशने के लिए प्रयास करेगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इस बैठक से सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग एवं घरेलू समर्थन पर कुछ सामने आने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र को लेकर जारी वार्ताओं में सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है। डब्ल्यूटीओ की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था माने जाने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक इस बार 30 नवंबर से शुरू होकर तीन दिसंबर तक चलेगी। इसमें डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा, '12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक करीब आने से कृषि क्षेत्र में जारी वार्ताओं को तेज करने के लिए कई प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। जी-33 समूह के साथ भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में लगा रहा है।' उन्होंने भारत के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग को जरूरी बताते हुए कहा कि भारत लंबे समय से इसी मांग करता रहा है और आगे भी अपनी आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि यह मसला दुनिया भर में करीब 80 करोड़ भूखे लोगों के निर्वाह से जुड़ा हुआ है। दरअसल डब्ल्यूटीओ मानकों के तहत किसी सदस्य देश का खाद्य सब्सिडी बिल उत्पाद मूल्य की 10 फीसदी सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत इस प्रावधान को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की राह में बाधा मानते हुए इसमें जरूरी बदलावों की मांग करता रहा है। अंतरिम व्यवस्था के तहत 2013 में संपन्न बाली मंत्रिस्तरीय बैठक ने अस्थायी छूट दी थी और भविष्य में इसका स्थायी समाधान निकालने की बात कही थी।

ईपीएफओ ने शेयरों में 1.23 लाख करोड़ के निवेश से कमाया 15% रिटर्न, छह करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

EPFO या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी इंइध कर्मचारी की अकस्मात मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को अब दोगुनी रकम दी जाएगी। केंद्रीय बोर्ड की तरफ से कर्मचारी की अचानक मौत होने पर उसके परिजन को एक्स ग्रेशिया डेथ रिलीफ फंड दिया जाता है।

EPFO को शानदार कमाई

पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में शानदार तेजी जारी है और इसकी मदद से एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ ने 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर 14.6% का सालाना रिटर्न कमाने में सफलता हासिल की है। ईपीएफओ की इस कमाई से देश के छह करोड़ वेतनभोगी लोगों

को खुश हो जाने की वजह मिल गई है। भारत सरकार के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मैनेजर ईपीएफओ ने पिछले कुछ समय से ही शेयरों में निवेश करना शुरू किया है। ईपीएफओ के निवेश से रिटर्न पर हालांकि भारत 22 और सीबीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश की वजह से थोड़ा असर पड़ा है।

भारत 22 ETF से मामूली रिटर्नकेंद्र सरकार ने भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के हिसाब से की थी। केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में विनिवेश के लक्ष्य को भारत 22 ETF के जरिए पूरा करने का प्लान बना रही थी। सीपीएसई ईटीएफ वास्तव में चुनिंदा पब्लिक सेक्टर कंपनी के प्रदर्शन के हिसाब से निवेश पर रिटर्न देती है। भारत 22 ईटीएफ में निवेश पर ईपीएफओ को सालाना सिर्फ 2.1 फीसदी का रिटर्न मिला है। अगर बात सीपीएसई ईटीएफ की करें तो इससे ईपीएफओ को 1.7 फीसदी नेगेटिव रिटर्न मिला है।

शानदार रिटर्न का दिखेगा असरविशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार में निवेश के बाद ईपीएफओ की शानदार कमाई की वजह से पीएफ अकाउंट रखने वाले निवेशकों को रिटर्न देने की इसकी क्षमता बढ़ी है। ईटीएफ जैसे कुछ निवेश विकल्पों में हुए नुकसान की वजह से ईपीएफओ के शेयर बाजार में निवेश स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाने की जरूरत है। EPFO में छह करोड़ से अधिक लोगों के पीएफ की रकम हर महीने जमा हो रही है।

SBI Mf ने दिखाया कमालअगर बात सीपीएसई ईटीएफ और भारत 22 ईटीएफ में ईपीएफ के निवेश की तुलना करें तो सीपीएसई ईटीएफ को एसबीआई म्युचुअल फंड संभाल रहा है जबकि भारत 22 ईटीएफ को यूटीआई म्युचुअल फंड संभाल रहा है। ईपीएफओ शेयर बाजार में सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए ही निवेश करती है। 31 मार्च 2021 को ईपीएफओ के कॉरपस में 15.76 फीसदी का रिटर्न मिला है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने nifty50 और सेंसेक्स सूचकांक की ईटीएफ में इस रकम का निवेश किया है।

चैरिटेबल ट्रस्ट को अनुदान, गैर-परोपकारी दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगाः एएआर

नयी दिल्ली। एजेंसी

महाराष्ट्र अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने कहा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट उनके द्वारा प्राप्त अनुदान और गैर-परोपकारी दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट जयशंकर ग्रामीण व आदिवासी विकास संस्था संगमनेर ने एएआर की महाराष्ट्र पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या वह केंद्र और राज्य सरकारों सहित विभिन्न संस्थाओं से दान/अनुदान के रूप में प्राप्त राशि पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में आयकर अधिनियम के तहत भी पंजीकृत है। यह ट्रस्ट महिला और बाल कल्याण के लिए काम करता है। यह अनाथ और बेघर बच्चों को आश्रय, शिक्षा, मार्गदर्शन, कपड़े, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है। महाराष्ट्र महिला एवं बाल कल्याण विभाग प्रति बच्चे प्रति माह 2,000 रुपये का भुगतान करता है। बच्चों के लिए अन्य खर्च दान से किए जाते हैं। एएआर ने अपने फैसले में कहा कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त अनुदान पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा।

वेदांत समूह अपने कारोबार का करेगा पुनर्गठन, बनाई निदेशकों की समिति

नयी दिल्ली। एजेंसी

अनिल अग्रवाल की अगुआई वाला वेदांत समूह पुनर्गठन पर विचार कर रहा है, जिसके तहत एल्युमिनियम, लोहा, स्टील और तेल एवं गैस कारोबारों के विघटन एवं उन्हें अलग-अलग इकाइयों के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा सकता है। समूह की अग्रणी कंपनी वेदांत लिमिटेड ने बुधवार को शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने समूह की पुनर्गठन योजना की समीक्षा करने एवं विकल्प सुझाने के लिए निदेशकों की एक समिति गठित की है। वेदांत के मुताबिक, उसके निदेशक मंडल ने तय किया है कि विभिन्न कारोबारों को उनकी प्रकृति, मात्रा एवं संभावित अवसरों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को कॉर्पोरेट संरचना की समग्र समीक्षा करनी चाहिए और सभी उपलब्ध विकल्पों पर गौर करना चाहिए। इसमें विलय, अधिग्रहण एवं रणनीतिक भागीदारी जैसे साधन भी शामिल हैं। समूह की कारोबारी संरचना के विस्तृत मूल्यांकन के बाद एल्युमिनियम, लौह एवं स्टील और तेल एवं गैस कारोबारों के लिए एक-एक अलग सूचीबद्ध कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। वेदांत के निदेशक मंडल ने पुनर्गठन की यह प्रक्रिया कॉरपोरेट संरचना को दुरूस्त करने, सभी हितधारकों के हित में और नया कारोबार जुटाने की मंशा से यह निर्णय किया है। इसके लिए बोर्ड ने निदेशकों की मदद के लिए कई सलाहकारों को भी नियुक्त किया है।

भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है 30 'प्रीडेटर' ड्रोन

3 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे पर मुहर जल्द

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र 'प्रीडेटर' ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को तैयार है। तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपये (तीन अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित व्यय होगा। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस एमक्यू-9बी ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) द्वारा अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी दिए जाने की संभावना है। उसके बाद प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नीत कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा।

अमेरिका के साथ मेगा-सौदे पर मुहर लगने की तैयारी

सूत्रों ने कहा कि कीमत और हथियार पैकेज सहित खरीद से जुड़े विभिन्न प्रमुख पहलुओं को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष तक अमेरिका के साथ मेगा-सौदे पर मुहर लगने की तैयारी है। भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव शीघ्र ही में डीएसी के सामने रखा जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, 'खरीद प्रक्रिया का पूरा प्रयास यह

है कि हम बहुत ही संतुलित निर्णय लेते हैं और इसलिए सभी पक्षों की राय ली जाती है। प्रक्रिया जारी है और हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसे जल्दी ही डीएसी के समक्ष लाया जाएगा।'

ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास- भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन की खरीद के लिए प्रस्ताव किया था और तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित रिमोट- संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम हैं। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने सहित कई मकसदों के लिए तैनात किया जा सकता है। 'प्रीडेटर' ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध और जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद ऐसे हथियारों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अमेरिका ने 2019 में भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी और एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों की भी पेशकश की थी। पिछले साल, भारतीय नौसेना को मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अमेरिका से दो 'प्रीडेटर' ड्रोन पट्टे पर मिले थे। गैर-हथियार वाले दो एमएक्यू-9बी ड्रोन एक वर्ष के लिए पट्टे पर दिए गए थे और उसकी अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने का विकल्प था।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।